विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) 8 तथा 9 जनवरी, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित विद्युत सम्मेलन में जो कार्य योजना अपनाई गई थी उसमें राज्य बिजली बोर्डों से संबंधित निम्न कार्य निष्पादन को भी शामिल किया गया था ताकि राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपर्याप्त संसाधन जुटाये जाने और निवल अचल परिसंपत्तियों पर सांविधिक निर्धारित 3% की दर से लाभ अर्जित करना सुनिश्चित किया जा सके ।

1. संयंत्र भार अनुपात में सुधार

2. पारेषण और वितरण संबंधी हानियों को मात्रा को कम करना

3. युक्तिसंगत टैरिफ

4. राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया राशियों का निपटान

5. विदेशी सहायता का समुपयोजन; और

6. विद्युत के उत्पादन एवं वितरण में निजी क्षेत्र की सहभागिता ।

हरियाणा में विद्युत संयंत्र

961. श्री रामजी लाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में कार्य न कर रहे बड़े ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है और इनके कार्य न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या राज्य में विदेशी सहायता से नये विद्युत संयंत्र लगाये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो किस देश से वित्तीय सहायता ली जा रही है; और इन पर कुल कितना धन खर्च होगा तथा इन परियोजनाओं से जिलावार कितना विद्युत उत्पादन होने का अनुमान है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) हरियाणा में सभी विद्यमान ताप विद्युत संयंत्र संतोषजनक रूप से कार्य निष्पादन कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टीपीसी) के फरीदाबाद गैस आधारित विद्युत केन्द्र चरण-i (400 मेगावाट) को वित्तीय सहायता हेतु के०एफ०डब्ल्यू० (जर्मनी) और ओ० ई०सी०एफ० (जापान) को प्रस्तुत किया गया है । दोनों में से अभी तक किसी भी द्वारा परियोजना का मूल्यांकन नहीं किया गया है । गैस कम मात्रा में उपलब्ध होने से संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट और संशोधित लागत अनुमान तैयार किये जाने आवश्यक हैं जोकि तैयार किये जा रहे हैं । एन.टी.पी.सी. का समयबद्ध (टाइम स्लाइस) प्रस्ताव जोकि विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है, में इस परियोजना को शामिल किया गया है ।

हरियाणा में ताप तथा पन बिजली संयंत्र

962. श्री रामजी लाल : क्या विद्युत मंत्री 18 अगस्त, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 4358 और 4359 के दिये गये उत्तरों को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार बड़े तथा छोटे ताप विद्युत संयंत्रों और पन बिजली विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी-कितनी है और प्रत्येक संयंत्र से कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है ;

(ख) क्या उपरोक्त विद्युत उत्पादन हरियाणा राज्य की बिजली की मांग/आवश्यकता को पूरा करता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो हरियाणा में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो०वी० रंगैया नायडू) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नवत् है:-

केन्द्र का नाम	विद्युत उत्पादन क्षमता (मे०वा०)	23-2-1993 को विद्युत उत्पादन (मे०वा०)
ताप विद्युत		
फरीदाबाद	165	146
पानीपत	650	310
जल विद्युत		
यमुना नहर	48	45

(ख) अप्रैल-जून, 1993 की अवधि के दौरान हरियाणा में ऊर्जा की कुल आवश्यकता 9545 मि०यू० थी जिसकी तुलना में ऊर्जा की उपलब्धता 9310 मि०यू० थी जो कि 2.4% सीमांत कमी का द्योतक है ।

(ग) अप्रैल, 92- जनवरी, 1993 के दौरान हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से 28.1 मि०यू० की सहायता उपलब्ध कराई गई ।

Lignite based power plant in Rajasthan

963. SHRI AJIT P. K. JOGI: SHRI CHHOTUBHAI PATEL:

Will the Minister of POWER be-pleased to state:

(a) whether a proposal for starting a lignite based power plant in Rajasthan has been approved by Government;

(b) if so, the details thereof;

(c) what are the reasons for delay in installing the plant;

(d) the time by which it is likely to! be made operational; and

(e) whether any such plant is also likely to be set up in other parts of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE' MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU); (a) to (d) A proposal for the installation of a Lignite Mine cum Power Project (2x120 MW) at Barsingsar, Rajasthan was sanctioned in April, 1991 at an estimated cost of Rs. 828.04 crores for implementation by the Neyveli Lignite Corporation (NLC), a public sector undertaking under the administrative control of the Ministry of Coal. Preliminary work in respect of this project has been taken up by NLC. Subsequently due to resource crunch the NLC was unable to proceed with this project and it was decided to set up this project in the private sector. M/s. Coleman and Associates (an Australian consortium) has been identified for the implementation of this project in the private sector. However, the Government of Rajasthan is yet to enter into a Memorandum of Understanding (MOU) with the consortium. Further progress would depend on the outcome of the interac- , tion between the consortium and the Government of Rajasthan. The commissioning schedule of the project would be known , only after the project is sanctioned and orders for the main plant and equipment have been placed on the suppliers.

(e) Kutch Lignite Project (2x70 MW), Gujarat; Neyveli Thermal Power Project (600 MW); Neyveli Second Mine Cut (680 MW) and Neyveli Second Mine Cut Stage-H (3x210 MW) are already in